

वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में 11 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने 2022 में हुई इस परीक्षा के फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है



लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोटा आगमन पर शहर भर में जगह-जगह उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बिड़ला के स्वागत के लिए शहर भर में स्वागत द्वार बनाए गये तथा स्वागत मंचों के जरिये पुष्प वर्षा भी की गई।

दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोटा पहुंचे ओम बिड़ला का भव्य स्वागत

हिंडोली से कोटा तक भव्य रोड शो, स्वागतद्वार बनाकर जगह-जगह शानदार स्वागत हुआ

जयपुर, 6 जुलाई (का.सं.)। लोकसभा में दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र कोटा-बूंदी पहुंचने पर ओम बिड़ला का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हैंडिऑउट से बूंदी के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र पहुंचने के बाद हिंडोली से बूंदी तक पहले चरण का रोड शो हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला खुले जीप में भाजपा के स्थानीय नेताओं के आम जनता का अभिवादन करते हुए हिंडोली से बूंदी की तरफ रवाना हुए। उनके स्वागत में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन की भीड़ उमड़ी, साथ में गाड़ियों का भी लंबा काफिला था। जगह-जगह उनका फूल बरसाकर और मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। बिड़ला के रोड शो का दूसरा चरण कोटा में हुआ। ओम बिड़ला

- रोड शो में शामिल लोगों ने ओम बिड़ला की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी थीं।
- भाजपा के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्पीकर बिड़ला को 51 किलो का पुष्पहार पहनाया तथा साफा पहनाकर शाल ओढ़ाया।
- बिड़ला के साथ, प्रदेश सरकार के मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर तथा क्षेत्र में भाजपा विधायकों ने भी रोड शो में शिरकत की।

लोकसभा में दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के दूसरे नेता हैं। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ कांग्रेस की सरकार के वक्त लोकसभा के दो बार अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार इस पद पर काबिज होने से ओम बिड़ला राजस्थान में भाजपा का बड़ा चेहरा बन कर उभरे हैं। कोटा संवाददाता के अनुसार,

छपी टीशर्ट पहन रखी थी। लोगों ने इस अवसर को एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया। कोटा शहर में विभिन्न संस्थाओं, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष का जोर के साथ स्वागत किया। जगह-जगह पर स्वागत द्वार व मंच बनाए गए और आतिशबाजी भी की गई। कोटा प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मोणा, प्रदेश मंत्री अनुसुइया, शिक्षामंत्री मदन दिलावर, ऊर्जामंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, रामगोपाल वैरवा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने लोकसभाध्यक्ष को साफा, शॉल, 51 किलो का पुष्पहार एवं श्रीराम मंदिर का चिन्ह देकर उनका भव्य स्वागत किया।

- आरोपियों ने हरेक अर्धवर्ष से 8 लाख रु. लिये थे।
- आरोपी मोबाइल में प्रश्न पत्र लाए थे तथा अर्धवर्षों को बोल-बोलकर जवाब लिखवाए गए थे।
- इन सभी अर्धवर्षों का वन रक्षक पद पर चयन हो गया था।

कोटा प्रवीण मालवीया व उसकी पत्नी सविता डोडियार ने बताया कि वनरक्षक भर्ती सूचना 2020 में निकली थी, जिसकी परीक्षा 13 नवंबर 2022 को दो बारियों में हो रही थी। सकन सिंह खडिया ने परीक्षा के एक दिन पहले फोन कर बताया कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले अर्धवर्षों से बात कर 8 लाख रुपये प्रति कैंडिडेट की व्यवस्था कर सकते हो तो उनको बुला लो, कल

की परीक्षा के पेपर लेकर आएंगे। इस पर मालवीया ने भीलकुआ निवासी छान पारी के माध्यम से सुक्राम पुत्र रमेश डामोर निवासी बगायचा थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक नका बड़ोदिया, सुभाष पुत्र रमेश डंडीर निवासी कोठारिया थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक नका टिमेडा, वीरसिंह पुत्र कन्हैयालाल कटारा निवासी नवागांव थाना कुशलगढ़, हाल अष्ट्याक राठमवि उलटन धरियावादा, शैला पत्नी ईश्वरलाल पणदा निवासी मगरदा थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक नका कुशलगढ़, निरमा पत्नी सुक्राम डामोर निवासी बकाचा थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक नका कुशलगढ़, शिल्पा पत्नी भावचंद मईडा निवासी नागदा बड़ी थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक रंजेंद्र डंगरा, संगीता पुत्री पवन कुमार गणसाि निवासी रोहिया रामसिंह थाना सज्जनगढ़, हाल वनरक्षक नका कुशलगढ़, ईश्वरलाल पुत्र नाथु पणदा निवासी मगरदा थाना कुशलगढ़ को शास्त्री नगर किराये के मकान में

कश्मीर में दो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुठभेड़ कुलगाम के मोदरगाम गांव में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में घेराबंदी और तलाश अभियान (कासे) चला रही थी।

एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, जब सेना की संयुक्त टीम पर गोलीबारी शुरू हुई तो अभियान एक मुठभेड़ में बदल गया। शुरूआती गोलीबारी में सेना की एलिट यूनिट का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को एक चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई।

केन्द्रीय बजट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विशेष सत्र आयोजित किया गया था। नए सांसदों ने शपथ ली और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।

मु.मंत्री भजनलाल ने जयपुर शहर के विभिन्न प्रोजैक्ट्स का निरीक्षण किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को हीरापुरा बस टर्मिनल (अजमेर रोड) पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मु.मंत्री ने, मानसरोवर से अजमेर रोड तक मैट्रो विस्तार के निर्माण कार्य का भी अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

जयपुर, 6 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन के आवागमन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का धरातल पर जायजा लेने के लिए शनिवार को जयपुर शहर के विभिन्न प्रोजैक्ट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य एवं व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से प्रोजैक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था, बैठने हेतु छायादार स्थान, सफाई व्यवस्था सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि आसक्त माह से बर्सां का संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण को एवं नगर निगम के अधिकारियों को मानसरोवर में भारी बारिश से होने वाली समस्याओं से बचाव के लिए पूर्व में ही माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना

- मुख्यमंत्री ने हीरापुरा बस टर्मिनल तथा जयपुर मैट्रो फेज प्रथम-डी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
- सांगानेर में, मु.मंत्री ने 300 बेड की क्षमता वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र करने का निर्देश दिया।
- मु.मंत्री आर.यू.एच.ए.सी. भी गए तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और वहाँ भर्ती मरीजों से भी बात की।

नहीं करना पड़े। शर्मा ने मानसरोवर में जयपुर मैट्रो फेज 1-डी के तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक मैट्रो विस्तार के प्रगति निर्माण कार्य का अवलोकन किया।

इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य का पूर्ण निरीक्षण किया जा सके। शर्मा इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (आरयूएचएस) पहुंचे। यहां उन्होंने मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर, आईसीयू कॉम्प्लेक्स, आई ओटी यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आरयूएचएस में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने, चिकित्सकों की नियुक्ति करने, मरीजों के परिजनों के उद्धार की उचित व्यवस्था करने के संबंध में निर्देश दिए।

काफी रोचक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कश्मीर भू-भाग में आती हैं। भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेगी, चुनावों में प्रचार व वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा।

संभावना है कि भाजपा, पूर्ववर्ती रियासत के डोगरा राजा महाराजा हरिसिंह की विरासत को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहेगी जिन्होंने भारत संघ में शामिल होने का फैसला किया था। भजपा पार्टी के प्रचार मुद्दों की रणनीति में पी.डी.पी. की महबूबा मुफ्ती को अनन्तनाग-राजीरी के चुनावों में हुए नुकसान को तथा अभी कुछ समय पूर्व समाप्त हुए लोकसभा चुनावों में हार के मुद्दे को धुनाना चाहती है।

भाजपा के करीबी सूत्रों का कहना है कि भाजपा चुनावों में जम्मू व कश्मीर बैंक घोटाला चुनाव प्रचार में रोशनी घोटाला कांड को भी उठाएगी।

अल्पसंख्यक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को 20 लाख रुपये की छात्रवृत्ति देती है।

तेलंगाना में रैवन्त रेड्डी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होने के बाद, अब पार्टी के नेता व कार्यकर्ता धीरे धीरे सही पक्ष को भाग्यमयी आ रहे हैं। बी.आर.एस. को जोर का झटका उस समय लगा जब शुक्रवार को विधान परिषद के छः एम.एल.सी. नेताओं ने एक प्रायवेट होटल में बैठक की और कांग्रेस में सम्मिलित होने का निर्णय किया। कांग्रेसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि "मध्य रात्रि को लगभग 1 बजे ये नेतागण तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ए.रेवन्त रेड्डी के आवास पर पहुंचे थे जो कुछ देर पूर्व ही नहीं दिल्ली से वापस आए थे, उनसे मिलकर इन नेताओं ने पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की।"

रेवन्त रेड्डी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और सभी छः नेताओं को तेलंगाना की ए.आई.सी.सी. प्रभारी दीपा दास मुशी, राज्य के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी एवं पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल कर लिया। बी.आर.एस. के छः विधायकों द्वारा दलबद्ध कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद 40 सदस्यीय विधान परिषद में सत्ताधारी पार्टी की

सदस्य संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है जबकि इस विपरीत बी.आर.एस. के विधायकों की संख्या 25 से डटकर 19 रह गई है। इसके अतिरिक्त, इसमें चार मनोनीत एम.एल.सी. हैं, जिसमें से दो सदस्य ए.आई.एम.आई.एम. से हैं तथा भाजपा एवं पी.आर.टी.यू. दोनों से एक-एक सदस्य हैं और एक निर्दलीय है जबकि दो सीट रिक्त चल रही हैं।

राज्य विधानसभा में, कांग्रेस पहले ही बी.आर.एस. के छः एम.ए.ए. को तोड़ चुकी है। पार्टी के विधायकी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री के.टी. रामाराव ने दलबद्ध करवाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। सोशल मीडिया एक्स पर डाली गई एक पोस्ट में के.टी.आर. ने कहा "दलबद्ध करना कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ जिसने इस मामले को लेकर संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करने का वादा किया था, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दलबद्ध कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने पर स्वतः अनौपचारिक रूप से मांग की गई है। के. केशव राव ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद राजस्थान की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रामाराव ने कहा कि वे इस निर्णय का स्वागत करते हैं परन्तु बी.आर.आस.

के उन विधायकों का क्या होगा जिन्होंने दलबद्ध किया और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था तथा उन आधा दर्जन अन्य विधायकों का क्या होगा जो दलबद्ध करके कांग्रेस से सम्मिलित हुए हैं?" के.टी.आर. ने यह भी पूछा और राहुल गांधी पर निशाना साधा कि क्या उन्होंने इसी तरह से संविधान को सही ठहराया है। के.टी.आर. ने अपने एक्स पोस्ट पर पूछा "यदि आप बी.आर.एस. के विधायकों से इस्तीफा नहीं ले सकते तो आप पर देश कैसे भरोसा करेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र अनुसार दसवीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है? यह कैसा न्याय पत्र है?" बी.आर.एस. ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में 39 सीटें जीती थी और सत्ता से बाहर हो गई। परन्तु उनकी संख्या छः विधायकों को कांग्रेस में दलबद्ध कर जाने के बाद कम हो गई और एक एम.ए.ए. की एक उदृष्टना में मृत्यु हो गई। 119 सदस्यों वाली विधानसभा में जिस समय विधानसभा का गठन हुआ था कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 65 थी जो अब बढ़कर 71 हो गई है।

गहलोत राज में राज्य भंडारण निगम द्वारा अरबों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुछ इस प्रकार तय की गई थी कि इन दोनों कंपनियों के अलावा कोई इस निविदा में भाग ही नहीं ले सके। हैरानी की बात यह थी कि इस टेंडर के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई थी, जिस पर अदालत ने टेंडर पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तत्कालीन गहलोत सरकार व राज्य भंडारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी को टेंडर देने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के अपेक्षित को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अदालत ने कुछ समय के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थाई रोक हटाया थी, इसी बीच विधानसभा में कंपनियों के साथ अनुबंध कर लिया। आज भी इस प्रकरण पर अंतिम फैसला आना शेष है।

राज्य सरकार को भेजी गई सी.ए.जी. रिपोर्ट -1 सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि, एम.ओ.यू. की शर्तों के क्लॉज 15 में लिखा है कि अनुबंधित कंपनी को सरकार द्वारा निर्धारित गोदामों की 70 प्रतिशत की उपयोगिता सुनिश्चित करनी थी। इस रिपोर्ट में भी माना गया कि इस शर्त की पालना नहीं करने पर, जुलाई 2023 तक राज्य सरकार को इस कंपनी से 64.08 करोड़ रुपये की पेनल्टी वसूलनी जानी थी, लेकिन इस रकम में से मात्र 46.54

करोड़ रु. ही वसूले गए, जबकि 17.64 करोड़ रु. अभी भी बकाया है। खास बात यह है कि दोनों कंपनियों को भंडारण निगम को 24.34 करोड़ रु. की बैंक गारंटी देनी थी, लेकिन इन कंपनियों ने मात्र 22.20 करोड़ रु. ही जमा करवाए। लेखाकारों ने भंडारण निगम अधिकारियों से इस बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि, यह प्रकरण अदालत में आबिंटेशन में है, इसका फैसला लंबित है। लेखाकारों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि, भंडारण निगम का यह जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने आगे यह भी टिप्पणी की है कि, जब वर्ष 2021-22 में ही पता चल गया था कि दोनों कंपनियां गोदामों की 70 फीसदी उपयोगिता सुनिश्चित करने में फेल साबित हो रही थी फिर वर्ष 2022 से 2024 तक इन कंपनियों के साथ राजस्व साझा का अनुबंध जारी क्यों रखा गया?

ऑडिट रिपोर्ट की शर्त 15 में यह भी तय था कि, भंडारण निगम और श्री शुभम लॉजिस्टिक के बीच राजस्व साझेदारी क्रमशः 71:29 फीसदी की रहेगी, परन्तु यह राजस्व 15:85 के क्रम में मिला। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि भंडारण निगम ने, श्री शुभम लॉजिस्टिक को 'एग्री लॉजिस्टिकल पार्क' (ए.एल.पी.) में 75.96 करोड़

रु. का बिजनेस दिया, इस कारण कंपनी के राजस्व का प्रतिशत 29 प्रतिशत के बजाय 85 पहुंच गया। इससे पता चलता है कि भंडारण निगम ने इन कंपनियों को जुलाई 2020 से मार्च 2023 के बीच 26.22 करोड़ का अतिरिक्त बिजनेस दिया। उल्लेखनीय है कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कि गोदाम किराया, संचारण व स्टाफ वेतन का 32 प्रतिशत निगम ने दोनों कंपनियों को वसूलने दिया, जो कि करीब 49.74 करोड़ रु. की रकम थी।

जब निगम प्रशासन से लेखाकारों ने इस संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया कि, ए.एल.पी. में 85 प्रतिशत बिजनेस देने का फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया था और ऐसा वर्ष 2010 से हो रहा है। लेखाकारों ने इस जवाब को भी संतुष्टिपूर्ण नहीं माना है।

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि, इन दोनों कंपनियों ने गोदामों में रखी गई कृषि उपज की एवज में 2430 करोड़ रु. का अपर्याप्त बीमा कराया, जिससे किरानों को फसल खराब की स्थिति में भारी नुकसान लेखाकारों ने भंडारण निगम से सवाल किया तो जवाब मिला कि प्रशासन ने दोनों कंपनियों को ई-मेल लिखा है और जवाब आने पर ऑडिटर्स

को बता दिया जायेगा। लेखाकारों की टिप्पणी है कि निगम प्रशासन का यह जवाब, इश्वरसे लागू करवाने का फैलियर साफ जाहिर करता है।

ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि, दोनों कंपनियों ने अनुसूध के मुताबिक अतिरिक्त भंडारण क्षमता को बनवाने और उपयोग की एवज में 9.41 करोड़ रु. की अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं करायी। लेखाकारों को इस मुद्दे पर विभागा ने जवाब दिया है कि, हमने दोनों कंपनियों को कई बार बैंक गारंटी जमा करवाने के लिए पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक भी यह लंबित है और प्रक्रिया जारी है। ऑडिटर्स ने इस जवाब को भी उपयुक्त नहीं पाया है। ऑडिट रिपोर्ट में टिप्पणी की गई कि एक वर्ष बीतने के बाद भी बैंक गारंटी वसूलनी नहीं होना भंडारण निगम का एक बड़ा फेलियर है।

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि, गोदामों पर सिक्यूरिटी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की एवज में कंपनियों से 4.17 करोड़ रु. का वेतन राशि वसूलने में भी भंडारण निगम फेल साबित हुआ है। इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दों में करीब 6 करोड़ रु. की वसूलनी नहीं की गई है।

दोनों कंपनियों की बैंक गारंटी उलतब्ध नहीं करनी और कृषि उपज के

स्टॉक का इश्वरसे नहीं करवाने और टेंडर की अन्य शर्तों की पालना नहीं करने पर उठे विवाद पर राज्य भंडारण निगम ने इन कंपनियों का भुगतान किया है। इससे बाद 3 आर.एस. 2023 को इन कंपनियों ने भंडारण निगम की सहमति से राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचकर आबिंटेंट की नियुक्ति करावा।

बताया जा रहा है कि आबिंटेंट ने फैसला दिया है कि, भंडारण निगम इन कंपनियों को भुगतान कर दे, इसके बाद कंपनियों को भुगतान कर दे, इसके बाद कंपनियों की अपनी शेष बैंक गारंटी विभागा को जमा करावा दें। हैरानी की बात है कि ऑडिटर्स की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद भी राज्य भंडारण निगम ने आबिंटेशन" के माध्यम से इस मामले का निपटारा क्यों करत का उचित समझा। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि, सी.ए.जी. ने अनु वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट्स में कंपनियों व भंडारण निगम की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए जाने के बावजूद भी आबिंटेंट द्वारा इस तरह का अवॉर्ड दिया गया, जिससे प्रतीत होता है कि कंपनियों को बहाल किया जा रहा है। वर्तमान में यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी लंबित है। इस प्रकरण में आबिंटेंट द्वारा दिए गए अवॉर्ड की भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अमेरिका में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गई। फिलाडेलफिया, बोस्टन और कनेक्टिकट में गोलीबारी की घटनाओं में तीन लोग मारे गए। क्वींस सेक्सन में एक अपार्टमेंट में आठ साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छुट्टी के दिन गोलीबारी में एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे।